TITLE CODE:- UPHIN51504

गरवी गुजरात

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 218
दि. 09.12.2025,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : ASHWANI KUMAR Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष चर्चा की शुरूआत की

■ प्रधानमंत्री ने कहा- वंदे मातरम ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को बल दिया

■ प्रधानमंत्री ने कहा- वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होते देखना हम सभी के लिए गर्व की बात है

■ प्रधानमंत्री ने कहा- वंदे मातरम वह शक्ति है जो हमें, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करती है

■ प्रधानमंत्री ने कहा- वंदे मातरम ने भारत में हजारों वर्षों से गहराई से जड़ें जमाए विचार को फिर से जागृत किया

■ प्रधानमंत्री ने कहा- वंदे मातरम में हजारों वर्षों की सांस्कृतिक ऊर्जा भी समाहित होने के साथ-साथ स्वतंत्रता का उत्साह और स्वतंत्र भारत का दृष्टिकोण भी शामिल था

■ प्रधानमंत्री ने कहा- लोगों के साथ वंदे मातरम का गहरा सम्बंध हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की यात्रा को दर्शाता है

■ प्रधानमंत्री ने कहा- वंदे मातरम ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को बल और दिशा दी

■ प्रधानमंत्री ने कहा- वंदे मातरम के सर्वव्यापी मंत्र ने स्वतंत्रता, त्याग, शक्ति, पवित्रता, समर्पण और लचीलेपन को प्रेरित किया

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज लोकसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर आयोजित विशेष चर्चा की शुरूआत की। प्रधानमंत्री ने इस महत्वपूर्ण अवसर पर सामूहिक चर्चा का मार्ग चुनने के लिए सदन के सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम, वह मंत्र और आ'न है जिसने राष्ट्र के स्वतंत्रता आंदोलन को ऊर्जा और प्रेरणा दी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया। इस सदन में वंदे मातरम को याद किया जाना सभी के लिए सौभाग्य की बात है। श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि यह गर्व की बात है कि राष्ट्र वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बन रहा है। उन्होंने कहा कि यह कालखंड हमारे सामने इतिहास की अनगिनत घटनाओं को लेकर आता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि यह चर्चा न केवल सदन की प्रतिबद्धता को दर्शाएगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा का स्रोत भी बन सकती है, बशर्ते सभी सामूहिक रूप से इसका सदुपयोग करें।

श्री मोदी ने कहा कि यह वह दौर है जब इतिहास के कई प्रेरक अध्याय एक बार फिर हमारे सामने आ रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि राष्ट्र ने हाल ही में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने का गौरवपूर्ण जश्न मनाया है। उन्होंने कहा कि देश सरदार वल्लभभाई पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी मना रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में राष्ट्र ने गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस मनाया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह सदन राष्ट्रगीत की सामूहिक ऊर्जा को अनुभव करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वंदे मातरम की 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से होकर गुजरी है। यह याद करते हुए कि जब वंदे मातरम के 50 वर्ष पूरे हुए थे, तब राष्ट्र अंग्रेजी शासन के अधीन रहने को विवश था, श्री मोदी ने कहा कि जब इसके 100 वर्ष पूरे हुए, तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उन्होंने बताया कि वंदे मातरम के शताब्दी समारोह के समय देश के संविधान का गला घोंटा गया था। उन्होंने यह भी कहा कि जब वंदे मातरम के 100 वर्ष पूरे हुए, तो देशभक्ति की राह पर जी-जान से चलने वालों को सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि जिस गीत ने देश की स्वतंत्रता को ऊर्जा दी, दुर्भाग्य से जब इसके 100 वर्ष पूरे हुए, तो उस समय इतिहास का एक काला अध्याय चल रहा था और लोकतंत्र स्वयं गंभीर तनाव में था।

श्री मोदी ने बल देकर कहा, "वंदे मातरम के 150 वर्ष उस महान अध्याय और गौरव को फिर से स्थापित करने का अवसर प्रस्तुत करते हैं, इसलिए सदन और राष्ट्र को इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए।" उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह वंदे मातरम ही था जिसने 1947 में देश को आजादी दिलाई और स्वतंत्रता संग्राम का भावनात्मक नेतृत्व इसके आ'न में समाहित था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वे 150वें वर्ष में वंदे मातरम पर चर्चा शुरू करने के लिए खड़े हुए, तो सत्ता पक्ष या विपक्ष में कोई मतभेद नहीं था, क्योंकि उपस्थित सभी लोगों के लिए यह वास्तव में वंदे मातरम के ऋण को स्वीकार करने का अवसर था। इसने लक्ष्य-उन्मुख नेताओं को स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। इसके परिणामस्वरूप हमें स्वतंत्रता मिली और आज सभी सदन में बैठ सकते हैं। उन्होंने बल देकर कहा कि सभी सांसदों और जनप्रतिनिधियों के लिए, यह उस ऋण को स्वीकार करने का एक पवित्र अवसर है। श्री मोदी ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने और पूरे देश - उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम - को एक स्वर में एकजुट करने वाली प्रेरणा, वंदे मातरम की भावना द्वारा एक बार फिर हमारा मार्गदर्शन करने पर बल दिया। उन्होंने सभी से स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा देखे गए सपनों को साकार करने के लिए मिलकर आगे बढ़ने और 150वें वर्ष में वंदे मातरम को सभी के लिए प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत बनाने का आ'न किया। उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण और 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने के संकल्प की पुनः पुष्टि करने का अवसर है।

श्री मोदी ने कहा कि वंदे मातरम की यात्रा 1875 में बंकिम चंद्र जी के साथ शुरू हुई। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि इस गीत की रचना ऐसे समय में हुई थी जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद, ब्रिटिश साम्राज्य अस्थिर था और उसने भारत पर तरह-तरह के दबाव और अन्यायपूर्ण नीतियां थोपकर, भारतवासियों को अधीनता स्वीकार करने पर विवश कर दिया था।

घुसपैठियों पर योगी का यूपी वासियों को खत, कहा- गैर जरूरी बोझ की समाप्ति भी जरूरी

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के निवासियों को संबोधित एक पत्र में कहा है कि घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं हैं। संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं। प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून-व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री योगी ने पत्र में लिखा- सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकती है। इससे स्पष्ट है कि घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं हैं। संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं।

यूपी की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता : उन्होंने पत्र में आगे कहा- यूपी की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून-व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। सभी नगरीय निकायों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक संसाधनों पर अनधिकृत बोझ की समाप्ति भी आवश्यक है। योजनाओं के माध्यम से वंचितों को मिलने वाले लाभ को बंटने नहीं दिया जा सकता है। इसी उद्देश्य से दस्तावेज सत्यापन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है और घुसपैठियों को चिह्नित कर उन्हें डिटेंशन केन्द्रों में भेजा जा रहा है, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

इसके लिए प्रत्येक मंडल में डिटेंशन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश की जागरूक जनता से अपील करता हूं कि सर्तक रहें और घरेलू अथवा व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पूर्व उसकी पहचान अवश्य सुनिश्चित करें। प्रदेश की सुरक्षा हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है क्योंकि सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है।

राष्ट्रीय डिजिटल संरक्षण नीति की आवश्यकता

राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन (एनएमएमए) एनएमएमए की डिजिटलीकरण नीति के अनुसार देश के असंरक्षित स्मारकों, स्थलों और पुरावशेषों का डिजिटलीकरण कर रहा है। राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारकों और स्थलों के लिए एकल पहुंच मंच के रूप में 'भारतीय विरासत' नामक उपयोगकर्ता-अनुकूल मोबाइल एप्लिकेशन के रूप में निर्मित विरासत का एक भंडार सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया है।

यह डिजिटल प्लेटफॉर्म राज्यों में संरक्षित राष्ट्रीय स्मारकों के उच्च-रिजॉल्यूशन छवियों, वास्तुशिल्प विवरण और जियो टैग किए गए स्थानों जैसी सुविधाओं के माध्यम से विरासत बनाने तक पहुंच प्रदान करता है।

डिजिटलीकरण संबंधित संगठनों की स्वीकृत और प्रकाशित नीति द्वारा निर्देशित होता है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कौशलों और गतिशीलता में सहयोग मजबूत करने का संकल्प दोहराया; खेलों, उन्नत विनिर्माण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर जोर

भारत ने एक समान मानकों के लिए वार्षिक भारत-ऑस्ट्रेलिया कौशल बैठक का प्रस्ताव किया

(जीएनएस)।

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कौशल विकास, कार्यबल गतिशीलता और तेजी से बढ़ती खेल अर्थव्यवस्था में सहयोग बढ़ाने के लिए अर्थपूर्ण आपसी विचार-विमर्श का आयोजन किया। इस बातचीत को नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया-भारत शिक्षा और कौशल परिषद की तीसरी बैठक के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया। द्विपक्षीय बैठक की अध्यक्षता कौशल विकास और उद्यमिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयंत चौधरी तथा ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा राज्यमंत्री और कौशल एवं प्रशिक्षण मंत्री श्री एंड्रयू जाइल्स (सांसद) ने संयुक्त रूप से की।

चर्चा के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में मजबूत बनाने पर सहमति जताई गई और कुशल पेशेवरों की आवाजाही के लिए इसे सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। दोनों देश योग्यता की पारस्परिक मान्यता को तेजी से लागू करने और ऐसे ब्रिज पाठ्यक्रमों को सह-डिजाइन करने पर सहमत हुए जो दक्षताओं के अनुकूल हों और और बिना किसी रुकावट के आवाजाही को आसान बनाएं। प्रमुख खेल आयोजनों से पहले ऑस्ट्रेलिया के बुनियादी ढांचे के विस्तार को देखते हुए, विशेष रूप से उन्नत निर्माण में कुशल श्रमिकों को वैश्विक मानकों के अनुसार तैयार करने पर जोर दिया गया।

इस दौरान भारत की 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की बोली और ऑस्ट्रेलिया के 2032 ब्रिस्बेन ओलंपिक और पैरालिंपिक की मेजबानी से उभरने वाले रणनीतिक अवसरों के बारे में भी चर्चा की गई। खेल और शारीरिक स्वास्थ्य क्षेत्र को सामूहिक रूप से एक उभरते हुए उद्योग के रूप में मान्यता दी गई, जिसमें रोजगार की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2% का योगदान दे सकता है। खेल प्रबंधन, खेल प्रौद्योगिकी में ऑस्ट्रेलिया के वैश्विक नेतृत्व को भारत के बढ़ते खेल विनिर्माण और गिग-इकोनॉमी परिदृश्य की एक पूरक शक्ति के रूप में पहचाना गया।

चर्चा में भारत के कौशल संस्थानों जैसे आईटीआई और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान और ऑस्ट्रेलिया के टीएएफइ नेटवर्क के बीच और सहयोग का प्रस्ताव रखा गया। खनन, डिजिटल और आईटी कौशल, आतिथ्य, ग्रीन जॉब्स, नवीकरणीय ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में संयुक्त रूप से काम करने की उम्मीद जताई गई।

श्री जयंत चौधरी ने 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम मेधा) की तैयारी के लिए कौशल' पहल के तहत भविष्य-उन्मुख कौशल के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। उन्होंने डिजिटल को अपनाने के लिए संयुक्त नैतिक ढाँचों और मानकों के महत्व पर बल दिया। मंत्रियों ने इस बात पर भी सहमति जताई कि ज़िम्मेदार और उच्च-गुणवत्ता वाली वर्कफोर्स मोबिलिटी को आगे चलकर द्विपक्षीय सहयोग का मार्गदर्शन करना चाहिए।

इस अवसर पर श्री जयंत चौधरी ने कहा, 'भारत और ऑस्ट्रेलिया भविष्य के वैश्विक कार्यबल को आकार देने में स्वाभाविक भागीदार हैं। मार्गों को मजबूत करके, मानकों को एक समान बनाकर और एक-दूसरे की क्षेत्रीय शक्तियों का लाभ उठाकर, हम युवाओं को वैश्विक अवसरों तक पहुँचने में सक्षम बना सकते हैं, साथ ही दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं में गतिशील उद्योग की जरूरतों का समर्थन भी कर सकते हैं। मैं वार्षिक भारत-ऑस्ट्रेलिया कौशल बैठक का प्रस्ताव रखता हूँ जिसका आयोजन बारी-बारी से भारत और ऑस्ट्रेलिया में किया जाए। यह मंच चयनित कौशलों में सामंजस्य और समकक्षता को बढ़ावा दे सकता है, संस्थागत साझेदारियों को गहरा कर सकता है और हमारे प्रशिक्षण परिवेश को दोनों देशों में उद्योग की जरूरतों के अनुकूल बना सकता है।'

मोटापा एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनकर उभरा है और यह केवल एक सौंदर्य संबंधी समस्या नहीं है : डॉ. जितेंद्र सिंह

'इसका समाधान वैज्ञानिक सटीकता एवं नीति अनुशासन के साथ करना चाहिए'

आईआईएसएफ पैनल ने मोटापे पर गलत सूचना की जांच वाले प्रावधानों की कमी पर प्रकाश डाला

डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत में तेजी से बढ़ती मे चयापचय चुनौतियों से निपटने के लिए नीतिगत अनुशासन की आवश्यकता पर बल दिया

(जीएनएस)।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (आईआईएसएफ) में "मोटापे पर चिकित्सक-वैज्ञानिक संवाद" विषय पर पैनल चर्चा में कहा, "मोटापा भारत में एक जन स्वास्थ्य चुनौती बनकर उभरा है और यह केवल सौंदर्य संबंधी समस्या नहीं है। इस चुनौती का समाधान वैज्ञानिक सटीकता एवं नीतिगत अनुशासन के साथ करने की आवश्यकता है।"

इस सत्र का आयोजन नैदानिक चिकित्सा, जैव चिकित्सा अनुसंधान और लोक नीति के प्रमुख विशेषज्ञों की उपस्थिति में किया गया। इस सत्र में भारत में बढ़ते चयापचय चुनौतियों पर एक बहु-विषयक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया। मंत्री ने आईआईएसएफ में खचाखच भरे दर्शकों को संबोधित करते हुए इस बात पर बल दिया कि कैसे सामाजिक व्यवहार, बाजार और गलत सूचनाओं ने भारत में मोटापे के परिदृश्य को जटिल बना दिया है।

मंच पर भारत के वैज्ञानिक एवं चिकित्सा समुदाय के प्रमुख विशेषज्ञ उपस्थित थे, जिनमें एनएबीआई के कार्यकारी निदेशक डॉ. अश्वनी पारीक; डॉ. विनोद कुमार पॉल और डॉ. वी.के. सारस्वत, सदस्य नीति आयोग; प्रो. उल्लास कोल्थुर, सीडीएफडी के निदेशक; टीएचएसटीआई के कार्यकारी निदेशक डॉ. गणेशन कार्तिकेयन; और वरिष्ठ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉ. संजय भदादा और डॉ. सचिन मित्तल शामिल थे।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय समाज में मोटापे को एक बीमारी के बजाय एक सौंदर्य संबंधी समस्या के रूप में देखा जाता है जिसके कारण इस पर वैज्ञानिक चर्चा में देरी हुई है। उन्होंने कहा, "दशकों से, हमारे चिकित्सा सम्मेलनों में मधुमेह एवं चयापचय संबंधी विकारों पर चर्चा होती रही है लेकिन मोटापे पर कभी नहीं हुई।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर में ग्रिट की गवर्निंग बॉडी की दूसरी बैठक संपन्न

● उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री तथा शिक्षा मंत्री बैठक में सहभागी हुए

● ग्रिट द्वारा विकसित किए गए 'विकसित गुजरात स्ट्रैटेजी रूम' का लोकार्पण ज्य के जिलों के 'डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडेक्ट एस्टीमेट्स' का अनावरण

● विकसित गुजरात@2047 तथा गुजरात@2035 का रोडमैप साकार करने में ग्रिट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

● रोजमर्रा के कार्य का डेटा ग्रिट में उपलब्ध है, फोकस एरिया में उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समन्वय स्थापित करें

● स्थापना के 15 महीने की अल्पावधि में युवा टीम के साथ ग्रिट रूप में स्थापित हुआ है

गांधीनगर, 08 दिसंबर :मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को गुजरात राज्य इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (जीआरआईटी-ग्रिट) की गवर्निंग बॉडी की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि ग्रिट विकसित गुजरात@2047 तथा गुजरात@2035 का रोडमैप साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि ग्रिट द्वारा विभागों के तथा विभिन्न योजनाओं के रोजमर्रा के कार्यों का डेटा उपलब्ध हो गया है। उसके प्रभावी क्रियान्वयन तथा कार्यों को अधिक गति देने के लिए यह डेटा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इसके परिणामस्वरूप विकसित गुजरात@2047 तथा गुजरात@2035 के लिए जिन विभागों पर अधिक फोकस करने की जरूरत है, उसे जानकर उस दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा।

सम्पादकीय

मिले समय का सुदपयोग न करने के चक्कर में आया यह एयरलाइन पर संकट!

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पिछले वुछ दिनों से भारी अव्यवस्था का सामना कर रही है। एक और उड़ानों का बड़े पैमाने पर रद्द होना तो दूसरी ओर आसमान छूते किराए ने यात्रियों की नाक में दम कर दिया है। एयरलाइन्स ने जिम्मेदारी नए एफडीटीएल (फ्लाइट डूटी टाइम लिमिटेशन) नियमों पर डाली, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इंडिगो के पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय था। इस कारण यह आरोप भी गंभीर हो गया है कि एयरलाइन ने नियमों में ढील पाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का रास्ता चुना। एविएशन विशेषज्ञों के अनुसार इस संकट की जड़ जनवरी 2024 में दायर उस याचिका में है जिसमें पायलट यूनियन ने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने थकान और लम्बी डूटी को गंभीर सुरक्षा जोखिम बताया था। कोर्ट के निर्देश के बाद डीजीसीए ने एफडीटीएल नियमों में बदलाव किए और उन्हें एक जुलाई 2025 से लागू कर दिया। इन नियमों में पायलटों को साप्ताहिक 36 घंटे की बजाए 48 घंटे का अनिवार्य आराम दिया और किसी भी छुट्टी को वीकली रेस्ट मानने पर रोक लगा दी। नवम्बर 2025 में इनका दूसरा चरण लागू हुआ, जिसमें लगातार नाइट शिफ्ट पर बड़ी पाबंदी लगा दी गई। इन्हीं बदलावों का असर इंडिगो पर सबसे अधिक पड़ा। 2 दिसम्बर को दिल्ली, मुंबई और बंगलुरू जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर उड़ाने अनियमित होना शुरू हुईं और ऑन टाइम परफॉर्मेंस (ओटीपी) गिरकर 35 प्रातिशत पर आ गया। 3 दिसम्बर को यह स्थिति और बिगड़ी और ऑन टाइम परफॉर्मेंस 19.7 प्रातिशत तक गिर गया। 4 दिसम्बर को हालात लगभग ठप हो गए। करीब 800 उड़ानें रद्द करनी पड़ी और ओटीपी सिर्प 8.5 प्रातिशत पर रह गया। कई रूट्स पर टिकट का किराया 10,000 से बढ़कर 40,000-50,000 तक देखा गया। क्या यह समस्या मोनोपॉली की वजह से हुई? साल 2006 के अगस्त में दिल्ली-मुंबई के बीच उड़ान से शुरू हुईं इंडिगो की कहानी इस मोड़ पर आ जाएगी तब राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, जिन्होंने 2005 में इंडिगो के मालिक इंटर ग्लोबल एंटरप्राइजेस की नींव रखी थी। आज भारत के विभिन्न बाजार में इंडिगो सबसे बड़ी खिलाड़ी है और इसके पास करीब 64 प्रातिशत हिस्सेदारी है। अब यही बढ़ा कद उसकी हजारों उड़ाने वैंसल होने और यात्रियों को हुई बेशुमार दिक्कतों के चलते सवालों के घेरे में हैं। संसद में भी इंडिगो की कथित मोनोपॉली यानि एकाधिकार पर सवाल उठे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि इस संकट के लिए वेंद्र का मोनोपॉली मॉडल जिम्मेदार है। विमानन क्षेत्र के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जो वुछ हुआ यह जानबूझ कर किया गया या बनाया गया। इस संकट से यह साबित होता है कि एक मोनोपॉली वंपनी जब चाहे देश को अपनी उंगलियों पर से नचा सकती है। सरकार ने एयर इंडिया को पीछे धकेल कर इंडिगो को एकाधिकार दिया जिससे वह विमानन क्षेत्र में मनमजा कर सके। जो वुछ हुआ है उससे यह छवि बनी है कि कोई एक बड़ी वंपनी भारत के विमानन नियमों में बदलाव करा सकती है। लिहाजा इस घटना से किसी एक वंपनी नहीं, बल्कि देश के पूरे विमानन क्षेत्र की साख पर आंच आई है। एविएशन सेफ्टी फर्म कंसलिटिग के सीईओ मार्व डी. मार्टिन ने कहा—एकाधिकार बड़ी वजह है। जिस तरह से यह मामला हुआ है उससे दुनिया भर में यह संदेश गया है कि भारत में एविएशन रेगुलेशन में दम नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र के एफएओ और भारत की साझेदारी से देश में नेक्स्ट जेन 'स्मार्ट ब्लू रिवॉल्यूशन', गुजरात के जखाऊ में भी बनेगा विश्वस्तरीय ब्लू हार्बर मॉडल

- जखाऊ (गुजरात), वनकबारा (दमन-दीव) और कराईकल (पुडुचेरी) में विकसित होंगे विश्वस्तरीय ब्लू हार्बर मॉडल
- PMMSY के तहत 452.32 करोड़ रुपये की स्मार्ट फिशिंग अवसंरचना परियोजनाएँ शुरू
- आगामी VGRC में कच्छ-सौराष्ट्र के तटीय विकास और ब्लू इकॉनमी पर रहेगा विशेष फोकस

गांधीनगर, 08 दिसंबर :गुजरात ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि भारत की ब्लू इकोनॉमी को नई ऊँचाइयों तक ले जाने की दिशा में उसका नेतृत्व सिर्फ दूरदर्शी ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक और परिणाम-केंद्रित भी है। तेजी से बदलते समुद्री परिदृश्य में आज फिशिंग हार्बर सिर्फ संरचनात्मक सुविधाएँ नहीं, बल्कि आर्थिक विकास, समुद्री आजीविका और तटीय समुदायों की समृद्धि के प्रमुख स्तंभ बन चुके हैं। इसी दृष्टिकोण के केंद्र में है गुजरात द्वारा विकसित की जा रही 'ब्लू हार्बर' अवधारणा, जो पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक दक्षता और सामाजिक समावेशन को एक साथ लेकर चलती है।

राष्ट्रीय स्तर पर भी तटीय अवसंरचना को नई गति देने के प्रयास तेज हो गए हैं। भारत सरकार ने हाल ही में मत्स्य विभाग (DoF), मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय (MoFAHD) और संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के साथ एक ऐतिहासिक तकनीकी सहयोग कार्यक्रम (TCP) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के तहत जखाऊ (गुजरात), वनकबारा (दमन-दीव) और कराईकल (पुडुचेरी) में विश्व-स्तरीय 'ब्लू

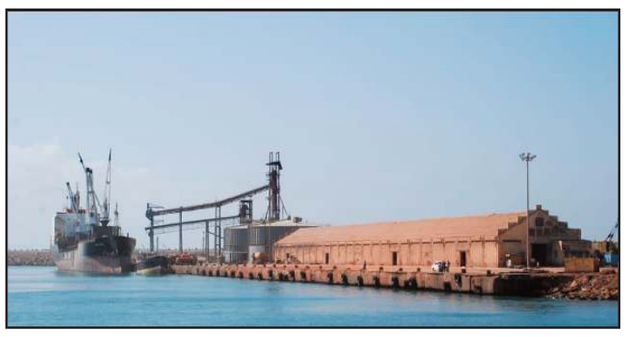

हार्बर' स्थापित किए जाएंगे जो देश में स्मार्ट, टिकाऊ और समावेशी मत्स्य अवसंरचना के नए राष्ट्रीय मानक गढ़ेंगे।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत 452.32 करोड़ रुपये के निवेश से स्मार्ट और एकीकृत फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएँ तटीय विकास को तेजी से बदल रही हैं। इन परियोजनाओं से न सिर्फ समुद्री मत्स्य व्यवसाय आधुनिक होगा बल्कि भारत के वैश्विक समुद्री-आहार बाजार में भी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बढ़ेगा।

कच्छ जिले के पश्चिमी छोर पर स्थित जखाऊ हार्बर गुजरात के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मत्स्य केंद्रों में से एक है और यह राज्य की ब्लू ग्रोथ विजन का प्रमुख आधार भी बना हुआ है। मत्स्य आयुक्त (COF) द्वारा प्रबंधित यह हार्बर हजारों मत्स्य-जीवियों के जीवन का केंद्र है और समुद्री सुरक्षा दृष्टि से भी अत्यंत रणनीतिक है। जेटी, मरम्मत क्षेत्र, भंडारण प्रणालियों और कटाई-परवर्ती सुविधाओं से लैस जखाऊ को हाल ही में 'ब्लू रिवॉल्यूशन' पहल में शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य इसकी अवसंरचनात्मक क्षमता को आधुनिक वैश्विक मानकों तक ले जाना है।

इसी पृष्ठभूमि में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (VGRC) जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह में राजकोट में आयोजित होने जा रही है। कच्छ और सौराष्ट्र जो अपने समृद्ध मत्स्य संसाधनों, महत्वपूर्ण समुद्री हार्बर्स और मजबूत तटीय अवसंरचना के लिए देशभर में प्रसिद्ध है, पर इस बार विशेष फोकस रहेगा । यह क्षेत्र न सिर्फ समुद्री मत्स्य क्षेत्र के गतिविधियों और वैल्यू-चेन लॉजिस्टिक्स के प्रमुख द्वार हैं बल्कि भारत की उभरती ब्लू इकोनॉमी के लिए भी महत्वपूर्ण इंजन बन रहे हैं। सम्मेलन में नीति-निमार्ताओं से लेकर उद्योग जगत के नेताओं, तकनीकी विशेषज्ञों और प्रमुख हितधारकों तक सभी एक मंच पर आएंगे जिसका उद्देश्य नए निवेश अवसरों, नवाचारों, उभरती तकनीकों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक साझा दृष्टि विकसित करना।

भारत ने पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन की उल्टी गिनती शुरू की

- केंद्रीय मंत्री श्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन के पूर्वावलोकन को संबोधित किया
- भारत पारंपरिक चिकित्सा के माध्यम से संतुलन बहाल करने में दुनिया में अग्रणी है: श्री प्रताप राव जाधव
- शिखर सम्मेलन पारंपरिक चिकित्सा के साक्ष्य-आधारित एकीकरण को प्रोत्साहन देगा: डॉ. पूनम खेत्रपाल
- वैश्विक शिखर सम्मेलन आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 17-19 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा
- शिखर सम्मेलन वैज्ञानिक सत्यापन, डिजिटल स्वास्थ्य, जैव विविधता संरक्षण और पारंपरिक चिकित्सा में वैश्विक सहयोग पर केंद्रित होगा

(जीएनएस)।

आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में द्वितीय विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन से पहले एक पूर्वावलोकन पर एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। यह शिखर सम्मेलन 17-19 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा।

केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री प्रतापराव जाधव ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि भारत 2023 में गुजरात में आयोजित पहले सफल आयोजन के बाद, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उन्होंने कहा कि यह शिखर सम्मेलन मानवता के स्वास्थ्य, खुशी और कल्याण के लिए पारंपरिक चिकित्सा को मुख्यधारा में लाने के सामूहिक वैश्विक प्रयास में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो भारत के "सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः" के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

श्री जाधव ने बताया कि इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय "संतुलन बहाल करना: स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास" है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के मंत्री, नीति निमार्ता, वैश्विक स्वास्थ्य नेता, शोधकर्ता, विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि और चिकित्सक एक साथ आएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इसमें 100 से अधिक देशों की भागीदारी अपेक्षित है।

केंद्रीय मंत्री महोदय ने घोषणा की कि आयुष मंत्रालय भारत के सबसे प्रसिद्ध और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किए गए औषधीय पौधों में से एक, अश्वगंधा पर एक समर्पित कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसमें पारंपरिक और समकालीन स्वास्थ्य पद्धतियों में इसके महत्व पर प्रकाश डाला जाएगा।

केंद्रीय मंत्री महोदय ने पारंपरिक चिकित्सा में भारत के वैश्विक नेतृत्व पर जोर देते हुए कहा कि आयुष प्रणालियाँ - आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी - सदियों से लोगों की सेवा करती रही हैं और आज समग्र स्वास्थ्य के लिए विश्वसनीय समाधान के रूप में दुनिया भर में मान्यता प्राप्त हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ साझेदारी में गुजरात के जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना, भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों में बढ़ते वैश्विक विश्वास को दशार्ती है।

श्री जाधव ने आगामी शिखर सम्मेलन की योजना बनाने में आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के निरंतर प्रयासों की प्रशंसा की और पारंपरिक चिकित्सा में जागरूकता बढ़ाने और जनता के विश्वास को मजबूत करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया।

केंद्रीय मंत्री महोदय ने बताया कि शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि शिखर सम्मेलन से प्राप्त विचार-विमर्श और सहयोग विश्व को स्वास्थ्य सेवा के अधिक समग्र, समावेशी और टिकाऊ भविष्य की ओर ले जाएंगे।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक एमेरिटस और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक की पारंपरिक चिकित्सा पर वरिष्ठ सलाहकार डॉ. पूनम खेत्रपाल ने इस बात पर जोर दिया कि पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग को आगे बढ़ाने में एक प्रमुख उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि 100 से अधिक देशों की भागीदारी के साथ, यह शिखर सम्मेलन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों में पारंपरिक, पूरक, एकीकृत और स्वदेशी औषधियों के साक्ष्य-आधारित, न्यायसंगत और सतत एकीकरण के लिए एक दशक लंबी रूपरेखा को आकार देगा।

पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक निर्भरता पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने अनुसंधान, नवाचार और नियामक सुदृढ़ीकरण के माध्यम से साक्ष्य अंतराल को पाटने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।

शिखर सम्मेलन के विचार-विमर्श के एक भाग के रूप में, "अश्वगंधा: पारंपरिक ज्ञान से वैश्विक प्रभाव तक - अग्रणी वैश्विक विशेषज्ञों के दृष्टिकोण" शीर्षक से एक केंद्रित कार्यक्रम 17-19 दिसंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। डब्ल्यूएचओ-जीटीएमसी द्वारा आयुष मंत्रालय के सहयोग से आयोजित यह सत्र अश्वगंधा की वैज्ञानिक समझ को मजबूत करने के लिए प्रमुख शोधकताओं, नीति निमार्ताओं और चिकित्सकों को एक साथ लाएगा। चचाओं में इसके एडाप्टोजेनिक, न्यूरोप्रोटेक्टिव और इम्यूनोमॉडुलेटरी गुणों पर समकालीन साक्ष्यों पर प्रकाश डाला जाएगा, साथ ही पारंपरिक ज्ञान से प्राप्त विचारों पर भी प्रकाश डाला जाएगा। सुरक्षा आकलन पर जोर देते हुए, इस सत्र का उद्देश्य उच्च-गुणवत्ता वाले, साक्ष्य-आधारित अश्वगंधा उत्पादों की वैश्विक स्वीकृति को और बढ़ावा देना है।

आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा; पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक श्री धीरेंद्र ओझा; आयुष मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री अलरमेलमंगई डी; आयुष मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री मोनालिसा दाश और आयुष मंत्रालय के उप महानिदेशक श्री सत्यजीत पॉल मंत्री के साथ मंच पर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में आयुष मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और मीडिया के सदस्य भी शामिल हुए।

पूर्वावलोकन कार्यक्रम 9-10 नवंबर 2025 को आयोजित राजदूतों के स्वागत समारोह के बाद आयोजित किया जा रहा है, जहाँ राजनयिकों को भारत-डब्ल्यूएचओ सहयोग और शिखर सम्मेलन के वैश्विक महत्व से अवगत कराया गया था।

आज के कार्यक्रम के साथ, भारत आधिकारिक रूप से पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन की उलटी गिनती शुरू कर रहा है, जो वैश्विक स्तर पर समग्र, एकीकृत और टिकाऊ स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

आईईपीएफए ने निवेशक- केंद्रित आउटरीच के माध्यम से भारत के वित्तीय जागरूकता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया है

सीएफएल पहल, वित्तीय साक्षरता शिविर, फेम आउटरीच और निवेशक दीदी योजना समुदायों में वित्तीय जागरूकता और सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा दे रही है

(जीएनएस)।

सरकार वित्तीय साक्षरता के लिए अनेक उपाय कर रही है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है :

१. वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) परियोजना की शुरूआत भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य वित्तीय साक्षरता के लिए समुदाय-आधारित नवीन और सहभागी दृष्टिकोण अपनाना है। देश भर में कुल 2,421 सीएफएल स्थापित किए गए हैं, जिनमें से एक सीएफएल औसतन तीन ब्लॉकों को कवर करता है।

२. बैंक अपने वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) के माध्यम से आम जनता के लिए यूपीआई और *99# (यूएसएसडी) के माध्यम से "डिजिटल होने" पर शिविरों का आयोजन करते हैं तथा विभिन्न लक्षित समूहों के लिए विशेष शिविरों का आयोजन करते हैं।

३. बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को प्रति माह एक शिविर आयोजित करना आवश्यक है, जिसमें वित्तीय जागरूकता संदेश (फेम) पुस्तिका के सभी संदेशों को शामिल किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बुनियादी बैंकिंग, डिजिटल वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण आदि सहित वित्तीय साक्षरता के विभिन्न पहलुओं पर संदेश शामिल होते हैं।

४. देश भर में जनता के बीच विभिन्न विषयों पर वित्तीय शिक्षा के संदेश का प्रचार करने के लिए 2016 से हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) का आयोजन किया जाता है।

५. आरबीआई का मल्टी-मीडिया, बहुभाषी जन जागरूकता अभियान, जिसका शीर्षक है "आरबीआई कहता है", वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने और सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं पर जनता को शिक्षित करने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करता है।

५. निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) द्वारा देश भर में निवेशक जागरूकता कार्यक्रम (आईएपी) चलाए जा रहे हैं। इन आईएपी के अंतर्गत, शिविरों का आयोजन करके वित्तीय साक्षरता और जागरूकता प्रदान की जाती है। "निवेशक दीदी" ऐसी ही एक पहल है, जिसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों और महिला मंडलों की सहायता से आंगनवाड़ियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), पंचायत भवनों और केवल महिलाओं के सम्मेलनों में शिविर आयोजित किए जाते हैं। निवेशक दीदी घरों और मोहल्लों में जाकर वित्तीय शिक्षा पहुँचाती हैं, खासकर दूर दराज के उन इलाकों में भी जहाँ आवाजाही सीमित है।

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) ने भारत भर में 68738 से अधिक लाभार्थियों तक पहुँचते हुए 1110 शिविरों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए "निवेशक दीदी" कार्यक्रम के तहत इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के साथ भागीदारी की थी। इस पहल की पहुँच और परिणाम को अखिल भारतीय स्तर पर विस्तारित करने के लिए 7 अप्रैल, 2025 को निवेशक दीदी चरण वक्क का शुभारंभ किया गया है। निवेशक दीदी चरण- वक्क में देश भर में महिलाओं सहित ग्रामीण और अर्ध-शहरी आबादी को लक्षित करते हुए जिम्मेदार निवेश, धोखाधड़ी की रोकथाम और डिजिटल बैंकिंग पर 4000 वित्तीय साक्षरता शिविरों की परिकल्पना की गई है। लगभग 40,000 महिला डाक कर्मचारियों को सामुदायिक वित्तीय शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह पहल जमीनी स्तर पर वित्तीय शिक्षा प्रदान करने के लिए डाक कर्मचारियों की व्यापक ग्रामीण उपस्थिति का लाभ दिलाती है।

यह जानकारी कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची

(जीएनएस)।

संस्कृति मंत्रालय संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (आईसीएच) की राष्ट्रीय सूची को समय-समय पर अद्यतन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है, जिसमें देश भर में आईसीएच तत्व के दस्तावेजीकरण, संरक्षण को शामिल किया गया है।

संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में कई योजनाएं लागू करता है। गुरु-शिष्य परंपरा योजना प्रदर्शन कला गतिविधियों की सभी शैलियों जैसे नाटक समूहों, थिएटर समूहों, संगीत कलाकारों, बच्चों के रंगमंच आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है और गुरु-शिष्य परंपरा के अनुरूप नियमित आधार पर कलाकारों को उनके संबंधित गुरु द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करती है। संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में भारत की लोक कलाओं और संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (जेडसीसी) स्थापित किए हैं। पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में मुख्यालय वाले ये केंद्र क्षेत्रीय सांस्कृतिक विविधता की रक्षा, प्रसार और विकास करने, युवाओं को शामिल करने और कला के लुप्त होते स्वरूपों का दस्तावेजीकरण करने के लिए काम करते हैं।

यूनेस्को के विनियम के अनुसार, यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए प्रत्येक दो वर्ष के चक्र में एक नामांकन प्रस्तुत किया जाता है। 2025-26 चक्र के लिए, दीपावली को आईसीएच सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया गया है। छठ महापर्व को साइकिल 2026-27 के लिए नामांकित किया गया है।

देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय के तहत 43 संगठन हैं। इनका ब्यौरा अनुलग्नक-क में दिया गया है। पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (ईजेडसीसी) विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पहलों का आयोजन करता है, जैसे कि "गुरु शिष्य परम्परा" योजना, जिसमें ओडिशा के पारंपरिक कला रूप जैसे गोटीपुआ नृत्य और पाइका अखाड़ा शामिल हैं।

भारत में वर्तमान में वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के कुंभ मेले सहित मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में 15 तत्व अंकित हैं। छठ महापर्व को वर्ष 2026-27 के लिए आईसीएच सूची के लिए नामांकित किया गया है। इन तत्वों का विवरण अनुलग्नक वक्क में दिया गया है।

पर्यटन मंत्रालय अपनी केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से बौद्ध पर्यटन के विकास के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकास कार्य के लिए 'बौद्ध सर्किट' की पहचान विषयगत सर्किटों में से एक के रूप में की गई है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) वार्षिक संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षित बौद्ध स्थलों सहित विभिन्न स्मारकों का संरक्षण और परिरक्षण करता है।

लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार: भारत के जम्मू-कश्मीर में ट्रांस-हिमालयी लद्दाख क्षेत्र, पवित्र बौद्ध ग्रंथों का मंत्रोच्चार आईसीएच की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में शामिल है।

केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के 'इंटरकनेक्शन मुद्दों पर ट्राई के मौजूदा विनियमों की समीक्षा' परामर्श-पत्र पर टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई

(जीएनएस)।

दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 10 नवंबर, 2025 को "इंटरकनेक्शन मुद्दों पर ट्राई के मौजूदा विनियमों की समीक्षा" विषय पर परामर्श-पत्र जारी किया। इस परामर्श-पत्र में उठाए गए मुद्दों पर लिखित टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां जमा करने की अंतिम तिथियां क्रमशः 8 दिसंबर, 2025 और 22 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई थीं।

उद्योग संगठनों और हितधारकों के समय बढ़ाने के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, परामर्श-पत्र पर टिप्पणियां देने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर दिसंबर, 2025 और प्रति-टिप्पणियों के लिए 29 दिसंबर, 2025 की गई है।

टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में श्री समीर गुप्ता, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग-क), ट्राई को ईमेल आईडी advnsll@trai.gov.in पर और एक प्रति ja2nsl2@trai.gov.in को भेजी जा सकती हैं।

किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए श्री समीर गुप्ता, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग-क), ट्राई से टेलीफोन नंबर +91-11-20907752 पर संपर्क किया जा सकता है।

ट्राई ने 'कुछ उपग्रह-आधारित वाणिज्यिक संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन हेतु नियम एवं शर्तें' पर दिनांक 09.05.2025 की अपनी सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग के दिनांक 12.11.2025 के संदर्भ का जवाब दिया।

(जीएनएस)।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज संचार मंत्रालय के, दूरसंचार विभाग (डीओटी) से प्राप्त दिनांक 12.11.2025 के संदर्भ पर अपना जवाब भेज दिया है। यह जवाब 'कुछ उपग्रह-आधारित वाणिज्यिक संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए नियम और शर्तों' पर ट्राई की दिनांक 09.05.2025 की सिफारिशों के संबंध में है।

इससे पहले, दूरसंचार विभाग ने दिनांक 11.07.2024 को एक संदर्भ के माध्यम से, ट्राई से अनुरोध किया था कि वह निम्नलिखित उपग्रह-आधारित संचार सेवाओं के लिए स्थलीय सेवाओं के साथ समान अवसर को ध्यान में रखते हुए स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण सहित स्पेक्ट्रम आवंटन के नियमों और शर्तों हेतु सिफारिशें प्रदान करे:

एनजीएसओ आधारित स्थिर उपग्रह सेवाएँ डेटा संचार और इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करती हैं। अपनी सिफारिशों में, ट्राई जीएसओ-आधारित उपग्रह संचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को ध्यान में रख सकता है।

जीएसओ/एनजीएसओ आधारित मोबाइल सैटेलाइट सेवाएं जो वायस टेक्स्ट, डेटा और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती हैं।

ट्राई ने एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया के बाद इस संबंध में, 09.05.2025 को 'कुछ उपग्रह-आधारित वाणिज्यिक संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए नियम और शर्तों' पर अपनी सिफारिशें दूरसंचार विभाग को भेजीं थी।

हाल ही में, दूरसंचार विभाग ने दिनांक 12.11.2025 के एक संदर्भ के माध्यम से, 'कुछ उपग्रह-आधारित वाणिज्यिक संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए नियम और शर्तों' पर ट्राई की कुछ सिफारिशों को संदर्भित किया है और ट्राई से अनुरोध किया है कि वह ट्राई अधिनियम 1997 (संशोधित) की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार, ऐसी सिफारिशों के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रदान करे।

ट्राई ने सावधानीपूर्वक जाँच के बाद, इस संबंध में, दूरसंचार विभाग के संदर्भ पर अपना जवाब भेज दिया है। संदर्भ पर ट्राई का जवाब ट्राई की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए ट्राई के नेटवर्क, स्पेक्ट्रम एवं लाइसेंसिंग सलाहकार श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी से टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR

पश्चिम रेलवे द्वारा मुंबई सेंट्रल - भगत की कोठी के बीच चलायी जाएगी स्पेशल ट्रेन

मुंबई, यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तथा यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से, पश्चिम रेलवे द्वारा मुंबई सेंट्रल और भगत की कोठी के बीच स्पेशल किराये पर एक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस स्पेशल ट्रेन का विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 09083/09084 मुंबई सेंट्रल झ भगत की कोठी साप्ताहिक स्पेशल (08 फेरे)

ट्रेन संख्या 09083 मुंबई सेंट्रल - भगत की कोठी साप्ताहिक स्पेशल प्रत्येक बुधवार को मुंबई सेंट्रल से 23:10 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 17:00 बजे भगत की कोठी पहुँचेगी। यह ट्रेन 10 से 31 दिसंबर, 2025 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09084 भगत की कोठी - मुंबई सेंट्रल साप्ताहिक स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार को भगत की कोठी से 11:30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 04:20 बजे मुंबई सेंट्रल पहुँचेगी। यह ट्रेन 12 दिसंबर, 2025 से 02 जनवरी, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, साबरमती, महेसाणा, पालनपुर, आबू रोड, फालना, मारवाड़, पाली मारवाड़ और लूनी स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, एसी-3 टियर (इकोनॉमी) कोच कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09083 की बुकिंग 09 दिसम्बर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

स्पेशल खेल महाकुंभ में 'वोरियर' टीम का शानदार प्रदर्शन, लगातार तीसरी बार गोल्ड मेडल पर कब्जा

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं गुजरात सरकार की प्रेरणा से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले विशेष खेल महाकुंभ में दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रतिभा ने एक बार फिर अपनी उड़ान भरी है। इसी कड़ी में श्री पराक्रमसिंह कनुभा गोहिल (कप्तान) के नेतृत्व में 'वोरियर' टीम ने पेरा सिटिंग वॉलीबॉल खेल की जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है।

यह प्रतियोगिता दिनांक 07/12/2025 (रविवार) को सिदसर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इनडोर स्टेडियम, भावनगर में पेरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन, भावनगर की अगुवाई में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में भावनगर जिले की कुल 7 टीमों ने भाग लिया, जिन सभी को पराजित करते हुए 'वोरियर' टीम ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। गौरतलब है कि 'वोरियर' टीम ने यह खिताब लगातार तीसरी बार जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित की है। यह उपलब्धि टीम की कड़ी मेहनत, अनुशासन और कप्तान श्री पराक्रमसिंह गोहिल के कुशल नेतृत्व का परिणाम है।

दिव्यांग कर्मचारी श्री पराक्रमसिंह कनुभा गोहिल वर्तमान में पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में वाणिज्यिक विभाग में मुख्य वाणिज्य क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं। अब जनवरी 2026 में श्री पराक्रमसिंह कनुभा गोहिल की अगुवाई में 'वोरियर' टीम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपने चैम्पियनशिप खिताब का बचाव (डिफेंड) करने हेतु नडियाद के लिए रवाना होगी।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा, अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री हिमाँशु शर्मा, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी, मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुश्री नीलादेवी झाला एवं भावनगर मंडल के सभी शाखा अधिकारियों ने उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई दी और भविष्य में उनकी शानदार उपलब्धियों की कामना की।

यूनेस्को की संस्कृति विभाग की सहायक महानिदेशक ने भारत सरकार को नई दिल्ली में इस समिति के 20वें सत्र की मेजबानी करने के लिए धन्यवाद दिया

संस्कृति मंत्रालय के सचिव ने कहा कि लाल किले में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर-सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी करना भारत की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अनोखे मेल को दशार्ता है

(जीएनएस)।

यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर-सरकारी समिति के 20वें सत्र की शुरूआत आज नई दिल्ली के लाल किले में विभिन्न सत्रों के साथ हुई। सुबह वाले सत्र के बाद संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री विवेक अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। 20वीं समिति (20 उडट) के चेयरपर्सन और यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, श्री विशाल वी. शर्मा, तथा यूनेस्को के संस्कृति विभाग के सहायक महानिदेशक, श्री एर्नेस्टो ओट्टोने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए श्री विवेक अग्रवाल ने कहा कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल लाल किले में इस सत्र की मेजबानी करना भारत की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अनोखे मेल को दशार्ता है। उन्होंने भारत के समुदाय-केन्द्रित दृष्टिकोण पर जोर दिया, जिसमें परंपराओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सूची का लगातार विस्तार, परंपरा-वहाकों के लिए क्षमता-निर्माण कार्यक्रम, और जीवित विरासत को राष्ट्रीय विकास योजनाओं में शामिल करने के प्रयासों को रेखांकित किया।

सचिव ने भारत के उन 15 तत्वों का भी ज़िक्र किया, जो यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में शामिल हैं—जैसे वैदिक मंत्रोच्चार, कुटियट्टम, योग, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा और गरबा। उन्होंने इन्हें 'भारत की सांस्कृतिक पहचान का रंगीन प्रतिबिंब' बताया। उन्होंने यह भी कहा कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मानवता की 'जीवित धड़कन' है, जो प्रदर्शन कलाओं, हस्तकला, त्योहारों, अनुष्ठानों और पीढ़ियों से चली आ रही मौखिक परंपराओं के रूप में समुदायों द्वारा जीवित रखी जाती है।

सचिव ने जोर देकर कहा कि यह सत्र एक बेहद महत्वपूर्ण समय पर हो रहा है, क्योंकि दुनिया भर की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत व्यापारिक दबावों, बदलते सामुदायिक ढांचे और तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल वातावरण जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यूनेस्को का मंच सहयोग, संवाद और सामूहिक संरक्षण के लिए बेहद आवश्यक है।

उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए श्री विशाल वी. शर्मा ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और सांस्कृतिक विरासतों की सुरक्षा के प्रति भारत की लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि समिति में भारत का वर्तमान कार्यकाल (2022झ 2026) जीवित विरासत की सुरक्षा पर वैश्विक चचाओं में भारत की भूमिका को और मजबूत करता है।

श्री एर्नेस्टो ओट्टोने ने भारत सरकार को नई दिल्ली में 20वें सत्र की मेजबानी के लिए धन्यवाद और खुशी व्यक्त की। साथ ही, उन्होंने सांस्कृतिक विरासतों की सुरक्षा में भारतीय सरकार के प्रयासों की सराहना की।

यह सप्ताहभर चलने वाला सत्र 8 से 13 दिसंबर 2025 तक आयोजित होगा, जिसमें सदस्य देशों, सांस्कृतिक संस्थानों, विशेषज्ञों, एनजीओ और पर्यवेक्षकों सहित लगभग हजार प्रतिनिधि शामिल होंगे।

अहमदाबाद मण्डल पर बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के 70वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल में आज मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय में आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में भारतीय संविधान के निमार्ता एवं भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के 70वें महापरिनिर्वाण दिवस पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

मण्डल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश, अपर मण्डल रेल प्रबंधक श्रीमती मंजू मीणा तथा अपर मण्डल रेल प्रबंधक श्री विकास गढ़वाल सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने डॉ. बी.आर.अम्बेडकर की छवि पर माल्यार्पण किया एवं दीप प्रज्वलित कर उन्हें नमन किया।

कार्यक्रम में मण्डल के रेल अधिकारी, ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि, ओबीसी एसोसिएशन, एससी/एसटी एसोसिएशन के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में रेल कर्मचारियों ने उपस्थित होकर डॉ. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की।

भावनगर रेलवे मंडल पर मनाया गया डॉ. भीमराव आंबेडकर जी का 70वाँ 'महापरिनिर्वाण दिवस'

पश्चिम रेलवे के भावनगर रेलवे मंडल पर भारत रत्न संविधान निमार्ता बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर का 70वाँ महापरिनिर्वाण दिवस श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाया गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि बाबा साहेब का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था, जिसे प्रतिवर्ष महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है।

दिनांक 06 दिसंबर 2025 (शनिवार) को मंडल कार्यालय में प्रशासनिक अवकाश होने के कारण यह कार्यक्रम 8 दिसंबर 2025 (सोमवार) को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, भावनगर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री हिमाँशु शर्मा सहित मंडल के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बाबा साहेब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा दो मिनट का मौन रखकर उनकी स्मृति को नमन किया।

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सभाकक्ष में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उनके योगदान को स्मरण किया।

इस अवसर पर भावनगर मंडल के विभिन्न ट्रेड यूनियनों, एससी/एसटी एसोसिएशन एवं ओबीसी एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में बाबा साहेब के विचारों, सामाजिक न्याय, समानता एवं संविधान के प्रति उनके अतुलनीय योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।

कार्यक्रम के माध्यम से बाबा साहेब के आदर्शों को आत्मसात करने तथा समाज में समता, बंधुत्व एवं न्याय के मूल्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया।

निर्माण कार्य के कारण भावनगर-साबरमती इंटरसिटी एक्सप्रेस आंशिक रूप से निरस्त

यात्रियों को सूचित किया जाता है कि रेल प्रशासन द्वारा ट्रेन नंबर 20966/20965 भावनगरझ साबरमतीझभावनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन में अस्थायी परिवर्तन को स्वीकृति प्रदान की गई है। साबरमती स्टेशन पर निर्माण कार्य प्रगति पर होने तथा ब्लॉक लिए के कारण यह ट्रेन दिनांक 16.12.2025 से 15.06.2026 तक गांधीग्राम और साबरमती स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

उक्त अवधि के दौरान ट्रेन का संचालन भावनगर से गांधीग्राम तथा गांधीग्राम से भावनगर के बीच ही किया जाएगा। गांधीग्रामझसाबरमतीझ गांधीग्राम खंड में इस ट्रेन का संचालन अस्थायी रूप से नहीं होगा।

यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व अपनी ट्रेनों की अद्यतन स्थिति की जानकारी रेलवे की अधिकृत वेबसाइट, 139 हेल्पलाइन अथवा नजदीकी रेलवे स्टेशन से प्राप्त कर लें।

रेल प्रशासन को असुविधा के लिए खेद है तथा यात्रियों के सहयोग की अपेक्षा करता है।

'मेरा गांव मेरी धरोहर' कार्यक्रम : चंपारण के गांवों का विवरण एमजीएमडी पर अपलोड

बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के सभी 1237 गांवों का विवरण एमजीएमडी पोर्टल पर मानचित्रण करके अपलोड किया गया है।

मेरा गांव मेरी धरोहर (एमजीएमडी) कार्यक्रम के तहत देश भर में सांस्कृतिक मानचित्रण के लिए 6,38,365 गांवों की पहचान की गई है। इनमें से अब तक 6,23,449 गांवों का विवरण एमजीएमडी पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।

अपनी दस्तावेजीकरण गतिविधियों के हिस्से के रूप में, एमजीएमडी, मौखिक परंपराओं, विश्वासों, रीति-रिवाजों, ऐतिहासिक महत्व, कला रूपों, विरासत स्थलों, पारंपरिक भोजन, प्रमुख कलाकारों, मेलों और त्योहारों, पारंपरिक पोशाक, गहने और स्थानीय स्थलों सहित मूर्त और अमूर्त दोनों सांस्कृतिक तत्वों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है।

एमजीएमडी कार्यक्रम प्रामाणिक, ग्राम-स्तरीय सांस्कृतिक प्रोफाइल बनाकर ग्रामीण पहचान को मजबूत करने पर जोर देता है जो स्थानीय परंपराओं, प्रणालियों और विरासत संपत्तियों को मान्यता देता है। यह एमजीएमडी पोर्टल के माध्यम से समुदाय के नेतृत्व वाले दस्तावेजीकरण और क्राउड-सोर्स्ड सत्यापन को सक्षम करके सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। एकल राष्ट्रीय पोर्टल पर संरचित सांस्कृतिक डेटा की उपलब्धता सांस्कृतिक क्लस्टर विकास, विरासत पर्यटन और पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने की योजना बनाने में सहायता करती है, जिससे स्थायी आजीविका सृजन और ग्रामीण आर्थिक विकास में योगदान मिलता है।

एमजीएमडी कार्यक्रम के तहत, संस्कृति मंत्रालय ने ओडिशा के गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण किया है, जिसके तहत अब तक 47,209 गांवों का मानचित्रण किया गया है। भद्रक जिले के सभी 998 गांवों का विवरण मैप किया गया है और एमजीएमडी पोर्टल पर अपलोड किया गया है। इसी तरह, बालासोर जिले के सभी 2,798 गांवों का विवरण मानचित्रण के बाद एमजीएमडी पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

भारत ने नई दिल्ली में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर-सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी की

प्रधानमंत्री के संदेश में अमूर्त विरासतों की सुरक्षा में यूनेस्को के प्रयासों की सराहना की गई

भारत जीवंत परंपराओं की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है: श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत

यूनेस्को की 20वीं अंतर-सरकारी समिति के साप्ताहिक सत्र का समापन 13 दिसंबर 2025 को होगा

(जीएनएस)।

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर-सरकारी समिति का 20वां सत्र नई दिल्ली के लाल किले में शुरू हो गया है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में केंद्रीय विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर यूनेस्को के महानिदेशक डॉ. खालिद अल-एनानी और यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत विशाल वी. शर्मा सहित कई वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री विवेक अग्रवाल ने इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री के संदेश में यूनेस्को के प्रयासों की सराहना की गई और सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने के लिए वैश्विक साझेदारों के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि भारत को यूनेस्को की सूची में शामिल चीजों पर गर्व है। हमें अपनी भाषाई विविधता, समृद्ध साहित्य और हमारे गांवों, कस्बों और समुदायों में पनप रही अनगिनत परंपराओं पर भी उतना ही गर्व है, जिनकी अपनी कहानी, इतिहास और मानवता के लिए अद्वितीय योगदान है।

केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि विरासत, स्मारकों और पांडुलिपियों से कहीं आगे बढ़कर है और यह भाषाओं, संगीत, त्योहारों, रीति-रिवाजों, शिल्प और मौखिक परंपराओं में बसती है। उन्होंने कहा कि भारत का सभ्यतागत मूल्य "वसुधैव कुटुम्बकम - विश्व एक परिवार है" आज भी उसकी सांस्कृतिक नीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मार्गदर्शन करता है।

केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत ने कहा कि आज भारत के 15 चीजें यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल हैं, जो देश की जीवंत और विविध जीवंत परंपराओं को दशार्ते हैं। विश्व स्तर पर, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में 150 देशों के 788 चीजें शामिल हैं, जो सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के पैमाने और तात्कालिकता को दशार्ता है।

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि समुदाय ही सांस्कृतिक विरासत के सच्चे संरक्षक हैं। उन्होंने शिल्प पुनरुद्धार, सामुदायिक अभिलेखीकरण, मास्टर-अप्रेंटिस प्रशिक्षण मॉडल और कारीगरों के लिए बाजार-आधारित आजीविका सहायता में भारत की पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्कूली पाठ्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सांस्कृतिक फेलोशिप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं की अधिक भागीदारी का आ'ान किया ताकि भावी पीढ़ियों के लिए परंपराओं की निरंतरता सुनिश्चित हो सके।

केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि समिति का 20वां सत्र वैश्विक सहयोग को मजबूत करेगा और व्यावहारिक, समुदाय-आधारित सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देगा। उन्होंने भारत में सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया और दुनिया भर में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए देश की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

उद्घाटन समारोह के बाद, प्रतिनिधियों ने शास्त्रीय, लोक और समकालीन परंपराओं को प्रदर्शित करते हुए भारतीय कला प्रदर्शनी देखी। इन प्रस्तुतियों में सांस्कृतिक जीवंतता और विविधता झलक रही थी जो भारत की जीवंत विरासत का मूल तत्व है।

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की प्रमुख पहल के रूप में ज्ञान भारतम

ज्ञान भारतम पहल

(जीएनएस)।

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की प्रमुख पहल के रूप में ज्ञान भारतम 1 फरवरी, 2025 को केंद्रीय बजट (पैरा 84) में घोषित किया गया। इसका उद्देश्य भारत की पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण, संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रसार करना है। इस पहल में एक करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को कवर करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकताओं के साथ सहयोग की परिकल्पना की गई है, जबकि पहुंच और वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा समर्थित एक राष्ट्रीय डिजिटल रिपॉजिटरी की स्थापना की गई है। इस पहल का समर्थन करने के लिए, स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) ने 2025-2031 की अवधि के लिए 491.66 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

ज्ञान भारतम डिजिटल वेब पोर्टल प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। 31 संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें से क्लस्टर केंद्रों के रूप में 19 केंद्र काम करेंगे और 12 केंद्र स्वतंत्र केंद्र के रूप में काम करेंगे, जो ज्ञान भारतम के पांच मुख्य कार्यक्षेत्रों: सर्वेक्षण और कैटलॉगिंग; संरक्षण और क्षमता निर्माण; प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण; भाषाविज्ञान और अनुवाद और अनुसंधान, प्रकाशन और आउटरीच में काम करेंगे। देश भर में क्लस्टर केंद्रों और स्वतंत्र केंद्रों का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी भागीदारों को अंतिम रूप दिया गया है। ज्ञान भारतम में लगभग 3.5 लाख पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है।

दिल्ली घोषणा (ज्ञान भारतम संकल्प पत्र) संस्थानों, विद्वानों, समुदायों और निजी संरक्षकों को एकजुट करके भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत को संरक्षित करने, डिजिटाइज करने और पुनर्जीवित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता निर्धारित करती है। भारत की सभ्यता की जीवंत स्मृति के रूप में पांडुलिपियों पर जोर देते हुए, यह पारंपरिक ज्ञान को समकालीन प्रासंगिकता में लाने के लिए आधुनिक संरक्षण प्रणालियों, बड़े पैमाने पर डिजिटल पहुंच और नए सिरे से अनुसंधान की मांग करता है। विरासत संरक्षण को एक जन आंदोलन में बदलकर और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर, यह घोषणा भारत को पांडुलिपि-आधारित शिक्षा के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए विविध लिपियों और ज्ञान परंपराओं की सुरक्षा में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाती है।

ज्ञान भारतम एक अखिल भारतीय पहल है और इसलिए, इसका दायरा देश के किसी विशिष्ट राज्य या क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। तदनुसार, ज्ञान भारतम पहल के तहत डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन - संगीत नाटक अकादमी, ओडिसी नृत्य, ओडिसी संगीत और संबलपुरी नृत्य सहित भारत की शास्त्रीय, पारंपरिक, आदिवासी और लोक प्रदर्शन कलाओं को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए उत्सवों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करती है। यह संगीत समारोहों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का भी आयोजन करता है और ओडिसी नृत्य और ओडिसी संगीत के कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जैसे राष्ट्रीय सम्मान प्रदान करता है।

संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन - पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (ईजेडसीसी), कोलकाता, ओडिशा सहित अपने सदस्य राज्यों की लोक कला को बढ़ावा देता है और नियमित रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्योहारों के माध्यम से संबलपुरी नृत्य (एक जीवंत लोक नृत्य रूप) का प्रदर्शन करता है।

केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

काशी तमिल संगमम्-4.0 का 7वाँ दिन; सांस्कृतिक कार्यक्रम में विभिन्न प्रस्तुतियों से दर्शकों में दिखा उत्साह

(जीएनएस)।

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, प्रयागराज एवं दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, तंजावूर, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित काशी तमिल संगमम 4.0 के सातवें दिन नमो घाट स्थित मुक्ताकाशी प्रांगण में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न हुआ, जिसमें तमिलनाडु एवं काशी के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दीं।

नमो घाट पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दर्शकों ने भाग लिया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देखकर वे भाव-विभोर हो उठे। जैसे-जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता गया, दर्शकों का उत्साह भी चरम पर पहुँचता गया। ठंड के बावजूद उपस्थित लोग कार्यक्रम का आनंद लेते रहे।

सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रथम प्रस्तुति डॉ. विजय कपूर एवं दल, वाराणसी द्वारा लोक गायन की रही। लोक शैली में कई भजनों की प्रस्तुति की गई, जिनमें प्रमुख थे— धर्म अपना सनातन हैङ्ग, हे शंभु तुम्हारी इच्छा परङ्ग, उठते ही सुबह खुद से कुछ बात कीजिएङ्ग, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आयाङ्ग। संगत में तबले पर पं. बलराम मिश्र, बांसुरी पर श्री सुधीर कुमार गौतम, साइट रिदम पर श्री संजय श्रीवास्तव तथा सह-गायन में सुश्री काजल तिवारी एवं सुश्री सुहानी शुक्ला शामिल रहीं।

द्वितीय प्रस्तुति डॉ. एस. ए. थनीकचलम, तमिलनाडु द्वारा पम्बई तमिल लोक वादन की रही। यह वादन देवी-पूजन परंपरा से जुड़ा हुआ है।

तृतीय प्रस्तुति सुश्री अदिति जायसवाल एवं दल, वाराणसी द्वारा लोक नृत्य की रही। उनके साथ नृत्य सहयोग में नेहा चौहान, अरुधंति जायसवाल, साक्षी कटवर, अराध्या केशरी एवं सुरभि कश्यप शामिल थीं।

चतुर्थ प्रस्तुति सुश्री अनन्या सिंह एवं दल, वाराणसी द्वारा कथक नृत्य की रही। इसमें कृष्ण वंदना तथा मेघ मल्हार की प्रस्तुति दी गई, जिसके बोल थे— गरज गरज। प्रस्तुत कलाकार थे— अनन्या सिंह, सौरभ दास, तनु कुमारी, कविता सिंह एवं अंजली कुमारी।

पंचम प्रस्तुति श्रीमती सुक्ला दत्ता एवं दल द्वारा कथक नृत्य की रही। इसमें प्रथम प्रस्तुति गंगा स्तुति की थी, जिसके बाद मीरा भजन प्रस्तुत किया गया तथा कार्यक्रम का समापन तराना से किया गया। नृत्य में कलाकार थीं— श्रीमती सुक्ला दत्ता, अनवेशा मुखर्जी, पारिजात गांगुली और श्रिया रॉय।

छठी एवं अंतिम प्रस्तुति श्री एन. आनंद वेलमुर्गन एवं दल, तमिलनाडु द्वारा देवराट्टम लोक नृत्य की रही। कार्यक्रम का संचालन श्री सौरभ चक्रवर्ती ने किया।

काशी तमिल संगमम् के अंतर्गत पुलिसकर्मी और नमो घाट पर रहने वाले परिवार सीख रहे हैं तमिल

(जीएनएस)।

काशी तमिल संगमम् 4.0 का इस वर्ष का मुख्य विषय 'तमिल सीखें झ तमिल करकलाम' है, जिसका उद्देश्य उत्तर और दक्षिण भारत के बीच भाषाई और सांस्कृतिक सेतु को और अधिक सशक्त बनाना है। इसी थीम के अंतर्गत वाराणसी में एक प्रेरणादायक और मन को छू लेने वाली पहल देखने को मिली।

एक ओर, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों ने तमिल भाषा का प्रशिक्षण लिया ताकि काशी आने वाले तमिलभाषी श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सहायता वे और भी सहज तथा प्रभावी ढंग से कर सकें। उन्हें दैनिक संवाद, अभिवादन तथा यात्रियों से सामान्य बातचीत के लिए आवश्यक तमिल वाक्य सिखाए गए।

वहीं, दूसरी ओर नमो घाट पर रहने वाले परिवार भी बड़े उत्साह और खुशी के साथ तमिल भाषा सीख रहे हैं। परिवार में मौजूद बच्चे इतने खुश थे कि तमिल में गिनती सीखते ही मुस्कुराते हुए जोर से दोहराने लगे— 'ओरु, रंडु, मून्नुङ्ग'—और एक-दूसरे को भी सिखाते नजर आए।

यह पूरा प्रशिक्षण आईआईटी मद्रास के डॉ. शिवा द्वारा संचालित विद्या शक्ति के तहत किया गया। उन्होंने सरल, संवादात्मक और परिवारों व पुलिसकर्मियों दोनों के लिए सहज रूप से सीखने योग्य शैली में तमिल का प्रशिक्षण दिया।

पुलिसकर्मियों और परिवारों दोनों का यह उत्साह और सहभागिता यह संदेश देती है कि काशी तमिल संगमम् केवल एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं, बल्कि 'तमिल करकलाम' के माध्यम से दो महान संस्कृतियों को जोड़ने वाला एक जीवंत और प्रभावशाली प्रयास है।

यूपीआई को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दुनिया का सबसे बड़ा रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम माना; ग्लोबल ट्रांजैक्शन में 49% हिस्सेदारी

पीआईडीएफ-समर्थित इंफ्रास्ट्रक्चर, भीम-यूपीआई इंसेंटिव और रूपे-यूपीआई विस्तार जैसे लक्षित उपायों से पूरे भारत में डिजिटल पेमेंट अपनाने में तेजी आ रही है

(जीएनएस)।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की जून 2025 की रिपोर्ट 'ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स (द वैल्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी)' में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) को ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट-पेमेंट सिस्टम (एफपीएस) माना गया है। इसके अलावा, एसीआई वर्ल्डवाइड की 2024 की रिपोर्ट 'प्राइम टाइम फॉर रियल-टाइम' के अनुसार, यूपीआई की ग्लोबल रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में लगभग 49% हिस्सेदारी है।

यूपीआई की वर्तमान स्थिति और अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय रियल-टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म की तुलना में मार्केट

शेयर का विस्तृत तुलनात्मक विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

यूपीआई सहित डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अपनाने में छोटे व्यापारियों की मदद करने के लिए, सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने समय-समय पर कई पहल की हैं। इनमें कम वैल्यू वाले भीम-यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम, और पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (पीआईडीएफ) शामिल हैं, जो टियर-3 से 6 केंद्रों में डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर (जैसे पीओएस टर्मिनल और क्यूआर कोड) लगाने के लिए बैंकों और फिनटेक कंपनियों को अनुदान सहायता प्रदान करता है। 31 अक्टूबर, 2025 तक, पीआईडीएफ के माध्यम से टियर-3 से 6 केंद्रों में लगभग 5.45 करोड़ डिजिटल टच पॉइंट लगाए गए हैं। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 तक, लगभग 6.5 करोड़ व्यापारियों को कुल 56.86 करोड़ क्यूआर कोड दिए गए।

सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और एनपीसीआई ने पूरे देश में सार्वजनिक सेवाओं, परिवहन और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सहित सभी बिजनेस में रूपे और यूपीआई के जरिए डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है।

सरकार और आरबीआई ने डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय किए हैं

(जीएनएस)।

देश में अनधिकृत डिजिटल लोन ऐप के कार्यान्वयन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और अन्य संबंधित नियामकों/ हितधारकों के साथ लगातार संपर्क में है। सार्वजनिक जानकारी के लिए, आरबीआई ने 01.07.2025 से अपनी वेबसाइट पर 'डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (डीएलए)' नामक एक निर्देशिका शुरू की है, जिसमें आरबीआई की विनियमित संस्थाओं (आरई) की ओर से तैनात सभी डीएलए शामिल हैं। इस निर्देशिका का उद्देश्य ग्राहकों को किसी डीएलए के किसी विनियमित संस्था से जुड़े होने के दावे की पुष्टि करने में मदद करना है।

अनधिकृत डिजिटल लेंडिंग ऐप्स की पहचान किए जाने के मामले में, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 69 ए के अंतर्गत सार्वजनिक पहुंच के लिए सूचना को ब्लॉक करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार है, जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी (जनता की ओर से

सूचना तक पहुंच को ब्लॉक करने के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 में दी गई प्रक्रिया का पालन करने के बाद किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार और आरबीआई समय-समय पर नागरिकों को अनधिकृत लेंडिंग ऐप के शोषण से बचाने के लिए कई पहल करते रहे हैं। इनमें दूसरी बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

आरबीआई ने 8 मई, 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक (डिजिटल लेंडिंग) निर्देश, 2025 जारी किए हैं। इन निदेशों में वसूली, डेटा गोपनीयता और ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र के बारे में विस्तृत प्रावधान हैं जो आरई, उनकी ओर से लगाए गए लेंडिंग सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) और डिजिटल लेंडिंग ऐप (डीएलए) के लिए अनिवार्य हैं।

अनधिकृत लेंडिंग ऐप के संचालन की समीक्षा के लिए प्रमुख इंटरनेट मध्यस्थों और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के साथ सक्रिय आधार पर संपर्क करना।

गृह मंत्रालय (एमएचए) का भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) डिजिटल लेंडिंग ऐप का सक्रिय होकर विश्लेषण कर रहा है। नागरिकों को अवैध लेंडिंग ऐप सहित साइबर घटनाओं की रिपोर्ट करने में सुविधा प्रदान करने के लिए, गृह मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के साथ-साथ एक राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर "1930" भी शुरू किया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने टीबी मुक्त भारत की दिशा में आगे बढ़ने के लिए राजस्थान के सांसदों के साथ बैठक की

इसी प्रकार की बैठक पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के सांसदों के साथ हुई

राजस्थान के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों ने मजबूत स्थानीय कार्यों और सामुदायिक सहभागिता से टीबी मुक्त भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की प्रतिज्ञा की

केंद्रीय मंत्री ने टीबी उन्मूलन में भारत के नेतृत्व को रेखांकित किया, प्रारंभिक पहचान, प्रौद्योगिकी-संचालित देखभाल और स्पर्शोन्मुख टीबी के बारे में नए साक्ष्य के आधार पर रणनीतिक बदलावों में नवाचारों पर प्रकाश डाला

राजस्थान के सांसदों ने जागरूकता बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण टीबी सेवाएं सुनिश्चित करने और टीबी मुक्त भारत के लिए एक सतत जन आंदोलन में समुदायों को संगठित करने की प्रतिबद्धता जताई

(जीएनएस)।

"टीबी मुक्त भारत" के लिए राजनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने के निरंतर प्रयास में, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान राजस्थान के सांसदों से मुलाकात की। यह सत्र विभिन्न राज्यों के सांसदों के साथ निरंतर चल रही ब्रीफिंग श्रृंखला का हिस्सा है जिसका उद्देश्य भारत में टीबी के विरुद्ध लड़ाई में सामूहिक नेतृत्व को मजबूत करना है।

आज के सत्र में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी, केंद्रीय रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू और राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले दोनों सदनों के सांसद नई दिल्ली स्थित संसद भवन एनेक्सी एक्सटेंशन में उपस्थित थे। विचार-विमर्श में टीबी, एक ऐसी बीमारी जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है, उन्मूलन की दिशा में भारत की तेज प्रगति में निर्वाचित प्रतिनिधियों की केंद्रीय भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

राजस्थान के सांसदों के नेतृत्व और भागीदारी की सराहना करते हुए, श्री नड्डा ने टीबी की जाँच और उपचार को सबके पहुँच में लाने के लिए राज्य की उपलब्धियों की सराहना की और बिना लक्षण वाले टीबी की चुनौती से निपटने के लिए निरंतर सतर्कता बरतने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि 2015 और 2024 के बीच भारत में टीबी के मामलों में 21% की गिरावट आई है, जो वैश्विक दर से लगभग दोगुनी है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार, देश में अब 90% उपचार सफलता दर दर्ज की गई है।

मंत्री महोदय ने सांसदों से ज़िला-स्तरीय कार्रवाई को मजबूत करने, निक्षय मित्रों को सहयोग देने और टीबी के कलंक को दूर करने तथा समय पर निदान और देखभाल सुनिश्चित करने के लिए समुदायों को संगठित करने में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा, "टीबी मुक्त भारत पहल इस बात का उदाहरण है कि कैसे राजनीतिक इच्छाशक्ति और जन भागीदारी मिलकर एक सदियों पुरानी जन स्वास्थ्य चुनौती का अंत कर सकते हैं।"

राजस्थान के सांसदों ने स्थानीय जागरूकता अभियानों का विस्तार करने, शीघ्र पहचान के लिए निक्षय शिविर आयोजित करने और अपने निर्वाचन क्षेत्रों में टीबी हस्तक्षेपों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। उन्होंने टीबी से प्रभावित लोगों को पोषण, मानसिक और आजीविका संबंधी सहायता प्रदान करने वाली सामुदायिक पहलों को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सरकार की रणनीतिक प्राथमिकताओं को रेखांकित किया, जिनमें समुदाय-आधारित स्क्रीनिंग को बढ़ाना, एआई-संचालित नैदानिक उपकरणों की शुरूआत और उपचार परिणामों को बेहतर बनाने के लिए पोषण-केंद्रित हस्तक्षेप शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, श्रीमती आराधना पटनायक ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत हुई प्रगति और आगे की राह का अवलोकन प्रस्तुत किया।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा के डिजिटल ट्विन को आईआईटी (दिल्ली) के उत्कृष्टता केंद्र के अंतर्गत मंजूरी

(जीएनएस)।

गंगा के डिजिटल ट्विन को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और सरकार की अन्य एजेंसियों में डेटा-आधारित निर्णय लेने में सहायता के लिए आईआईटी (दिल्ली) के उत्कृष्टता केंद्र के अंतर्गत मंजूरी दी गई है। जल विज्ञान मॉडलिंग, भूजल में कमी का आकलन, हॉटस्पॉट की पहचान, परिदृश्य विश्लेषण और बेसिन जल संसाधनों की निगरानी इस परियोजना के मुख्य कार्य हैं, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। परियोजना की कार्य-योजना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, गणितीय सिमुलेशन और नियोजन उपकरणों के उपयोग की परिकल्पना की गई है।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के अंतर्गत हाइब्रिड एन्युटी आधारित सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाएँ सीवरेज अवसंरचना के लिए एक नवोन्मेषी वित्तपोषण दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भुगतान को सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) के वास्तविक कार्य निष्पादन से जोड़ना है। एनएमसीजी द्वारा हाइब्रिड एन्युटी पीपीपी मोड के अंतर्गत 361.86 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी नगर निगम में महानंदा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए इंटरसेप्शन एंड डायवर्जन (आई एंड डी) और एसटीपी के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी गई है।

परंपरागत रूप से, संचालन और

रखरखाव (ओ एंड एम) चरण के दौरान यह दुविधा रहती थी कि, निजी संचालक उचित संचालन और रखरखाव पर कम ध्यान देते थे क्योंकि निर्माण चरण के दौरान प्राप्त होने वाले बड़े भुगतानों की तुलना में मासिक भुगतान अपेक्षाकृत कम होता था। इसके परिणामस्वरूप कभी-कभी गैर-अनुपालन और खराब प्रचालन प्रतिक्रिया होती थी।

इस मुद्दे के समाधान हेतु एक नया वित्तपोषण मॉडल विकसित किया गया है, जिसमें निर्माण भुगतान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्थगित कर दिया जाता है और एसटीपी के संतोषजनक कार्य निष्पादन के आधार पर ओ एंड एम चरण के दौरान लागत का केवल 40% भुगतान करती है। शेष 60% पूंजीगत लागत रियायत लेने वाले को 15 वर्ष की संचालन एवं रखरखाव अवधि में वार्षिकी के रूप में ब्याज सहित दी जाती है। यह संरचना सुनिश्चित करती है कि सरकार और निजी क्षेत्र, दोनों वित्तीय जोखिम को साझा करें। रियायत लेने वाले का मूल्यांकन रियायत समझौते में परिभाषित विशिष्ट प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) के आधार पर किया जाता है, और वार्षिकी भुगतान केवल तभी जारी किए जाते हैं जब कार्य निष्पादन के मानक पूरे हो जाते हैं।

इन परियोजनाओं में कोई उपयोगकर्ता शुल्क या शुल्क संग्रह शामिल नहीं है। पूरी परियोजना लागत सरकार द्वारा वहन की जाती है और राज्य सरकार को केंद्रीय अनुदान सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान को भागीरथी और अलकनंदा बेसिन (देवप्रयाग तक) में एक वास्तविक समय निगरानी नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से ग्लेशियर पिघलने संबंधी अध्ययन अनुमोदित किया गया है, जिसमें सभी प्रमुख धाराएँ और संबंधित प्रमुख ग्लेशियर क्षेत्र जैसे गंगोत्री, सतोपंथ, खतलिंग, पिंडर, चोराबाड़ी आदि शामिल होंगे।

इस परियोजना में उपग्रह डेटा, क्षेत्रीय अवलोकन और एसपीएचवाई मॉडलिंग का उपयोग करके ग्लेशियर द्रव्यमान संतुलन, पिघले हुए अपवाह का योगदान और जलवायु परिवर्तन प्रभावों का आकलन, और एनएमसीजी के लिए एक वेब-जीआईएस डैशबोर्ड को विकसित करना शामिल है। परियोजना के परिकल्पित उद्देश्यों में परियोजना के अंतर्गत उत्पन्न डेटा का उपयोग करके ग्लेशियरों पर बढ़ते तापमान के प्रभावों और जोखिमों का आकलन करना शामिल है।

यह सूचना जल शक्ति राज्यमंत्री श्री राज भूषण चौधरी द्वारा राज्यसभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में प्रदान की गई है।

केंद्र सरकार द्वारा अपनी ओर से भूजल स्तर बढ़ाने के लिए कार्यक्रम

(जीएनएस)।

सरकार विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देकर और मजबूत संरक्षण प्रयासों के माध्यम से देश के जल और भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन और विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, यह समझा जाना चाहिए कि 'जल' राज्य का विषय होने के कारण, जल और भूजल संसाधनों का सतत विकास और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार, अपनी ओर से, अपनी विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता देकर राज्य सरकारों के प्रयासों को सुविधाजनक बनाती है। देश के अति-दोहित , गंभीर और अर्ध-गंभीर क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ इस दिशा में उठाए गए प्रमुख कदम और उनकी उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

१. देश के जल/भूजल संसाधनों को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के प्रयास मुख्य रूप से जल शक्ति अभियान के प्रमुख अभियान के माध्यम से किए जाते हैं। जल शक्ति अभियान ,2019 से जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला एक समयबद्ध और मिशन मोड कार्यक्रम है। इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के तहत सभी प्रयासों और निधियों का अभिसरण किया जाता है ताकि जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण कार्य किए जा सकें।

वर्तमान में, जल शक्ति अभियान,2025 देश में चल रहा है, जिसमें अति-दोहित और गंभीर श्रेणी वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, जेएसए के तहत, पिछले 4 वर्षों में देश में अभिसरण के माध्यम से लगभग 1.21 करोड़ जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण कार्यों को पूरा किया गया है, जिसने भूजल संसाधनों की स्थिरता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जल शक्ति अभियान की गति को और मजबूत करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भारत में जल स्थिरता के लिए 'जल संचय जन भागीदारी: एक समुदाय-संचालित मार्ग' का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य

जल शक्ति अभियान
संचय जल, बेहतर कल

वर्षा जल संचयन को देश में एक जन आंदोलन बनाना है। सामुदायिक स्वामित्व और जिम्मेदारी को बढ़ावा देकर, यह पहल विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट जल चुनौतियों के अनुरूप लागत प्रभावी, स्थानीय समाधान विकसित करना चाहती है।

जल शक्ति मंत्रालय ने अटल भूजल योजना के माध्यम से समुदाय के नेतृत्व वाले सहभागी भूजल प्रबंधन की प्रभावकारिता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है, जिसे 7 राज्यों के 80 जल-संकट वाले जिलों में लागू किया गया था।

योजना के तहत प्रोत्साहन निधि के उपयोग और अभिसरण के माध्यम से विभिन्न वर्षा जल संचयन और पुनर्भरण संरचनाओं जैसे चेक डैम, तालाब, शाफ्ट आदि के निर्माण के साथ-साथ सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, योजना कार्यान्वयन के क्षेत्र में लगभग 83,000 संरचनाओं का निर्माण किया गया और 9 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को कुशल सिंचाई प्रथाओं के अंतर्गत लाया गया।

शहरी क्षेत्रों में जल संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा अमृत और अमृत 2.0 योजनाओं को लागू किया जा रहा है। ये शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रमुख पहल हैं, जो उन्हें 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनाने में सक्षम बनाती हैं।